नईदुनिया

संपादकीय

चीन के साथ पिघली अवरोध की बर्फ

यह हकीकत है कि चीन भौगोलिक रूप से हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। ऐसे में जरूरी है कि तमाम विसंगतियों के बावजूद अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के साथ पड़ोसी से रिश्ते बेहतर बनाए जाएं। लंबी खटास व तनातनी के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में हुई हालिया बैठक के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। बीजिंग में डोभाल व वांग तथा दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक निश्चित रूप से कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण प्रगति कही जा सकती है। खासकर 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद पांच वर्षों में यह पहली बातचीत, दो एशियाई दिग्गजों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण व सतर्क बदलाव को ही दर्शाती है। दरअसल, इस चर्चा का केंद्र लद्दाख पर अक्तूबर 2024 के समझौते का कार्यान्वयन था। यह सुखद ही है कि दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति बनाये रखने की प्रतिबद्धता जतायी। निश्चय ही यह कदम भविष्य में संघर्षों को रोकने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में सीमा व्यापार बढ़ाने, सीमा पार नदियों का डेटा साझा करने तथा कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से शुरू करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहन करने के उद्देश्य से छह सत्री सहमति पर भी जोर दिया गया। हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की सहमति से सारी चुनौतियां एकदम खत्म हो चुकी हैं। निर्विवाद रूप से सीमा विवाद एक संवेदनशील व जटिल मुद्दा बना है। जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आपसी विश्वास में व्याप्त कमी को दूर किया जाए। निश्चित रूप से व्यावहारिक कूटनीति के साथ विश्वास निर्माण के उपायों को कदम दर कदम बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इन प्रतिबद्धताओं को अमलीजामा पहनाने के लिये सतर्कता के साथ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी।

बहरहाल, खट्टे-मीठे रिश्तों और लंबी कटुताओं के बावजूद इस बैठक के निहितार्थों को व्यापक संदर्भों में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निर्विवाद रूप से चीन आज दूसरी बड़ी वैश्विक शक्ति है। भारत ने भी आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। इसके बावजूद दोनों ही देश वैश्विक शक्ति की बदलती गतिशीलता से जूझ रहे हैं। खासकर अमेरिका में होने जा रहे राजनीतिक परिवर्तन से उबरने वाली आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर। ऐसे में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को दोनों देशों की एकजुटता प्रभावित करने की क्षमता रखती है। खासकर व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों में सहयोगात्मक पहल से क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नि:संदेह, दोनों देशों की सीमा पर शांति की पहल एक शुरुआत मात्र है। इसके उपरांत दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क, व्यापार बाधाओं व असंतुलन को दूर करना वक्त की जरूरत है। हमें सांस्कृतिक सहयोग के जरिये दोनों देशों के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का लाभ उठाना चाहिए। विश्वास कायम करने और संघर्ष की छाया दूर करने के लिये ऐसे सकारात्मक कदम जरूरी हैं। नि:संदेह, रिश्तों को सामान्य बनाने का रास्ता लंबा है, लेकिन सार्थक संवाद से अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की आशा लगातार बनी रहती है। भारत और चीन के लिये शांति सिर्फ एक आदर्श मात्र नहीं बल्कि एक अपरिहार्य आवश्यकता है। निस्संदेह, भारत और चीन के बीच हुई यह तेईसवीं मुलाकात नई उम्मीद जगाती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच यह बातचीत कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद लिए गए फैसले के अनुरूप ही हुई है। जिसमें सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की बहाली और सीमा विवाद का उचित समाधान तलाशने पर सहमति बनी थी। उम्मीद की जानी चाहिये कि संक्रमण के दौर से गुजर रहे वैश्विक परिदृश्य में भारत व चीन एकजुट होकर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यह स्थिति दोनों देशों के हित में ही कही जाएगी।

सच ही है, आंबेडकर जी सम्मान का विषय, फैशन के नहीं

प्रवीण गुगनानी

संविधान पर चर्चा में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में जो कहा उसके पहले 11 सेकंड के अंश को भ्रामक रूप से देशभर में फैलाया जा रहा है। इससे कांग्रेस, आंबेडकर जी को फैशन का विषय मानने के अपने चिर पुराने चरित्र को ही दोहरा रही है। गृहमंत्री के इस वक्तव्य को यदि पूरा सुनेंगे तो आंबेडकर जी के अपमान के सारे वहम दूर हो जाते हैं। अमित शाह ने कहा- हमे तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ-साथ आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये भी बताता हूं। आंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा।

भाजपा के डीएनए में प्रारंभ से ही दलित विमर्श रहा है, क्योंकि इसका मातृ संगठन आरएसएस प्रारंभ से ही सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलने वाला संगठन रहा है। आंबेडकर जी, संत पेरियार, महात्मा फुले, नारायण स्वामी जैसे दलित महापुरुष संघ के प्रतिदिन होने प्रात: स्मरण मंत्र में सम्मिलित हैं। संघ के स्वयंसेवक जो भाजपा के कार्यकर्ता बनते हैं वे प्रतिदिन अपने प्रात: स्मरण के मंत्र में आंबेडकर जी का नाम श्रद्धा से लेते हैं। संघ के वरिष्ठ प्रचारक और विश्व के सबसे बड़े मजदूर नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी तो बाबासाहेब के चुनाव में आधिकारिक एजेंट की भूमिका में रहे हैं। इस तथ्य से आप उस कालखंड में संघ व आंबेडकर जी की म्यूचुअल अंडरस्टेंडिंग समझ सकते हैं। संघ के मूल चिंतन में दलित चिंता सदैव रही है, इसका परिणाम है कि मुंबई में जिस स्थान पर भाजपा का जन्म हुआ, उस स्थान का नाम संघ के प्रचारकों ने समता नगर रखा था। यह नाम एक बड़ा प्रतीक था भाजपा के दलित चिंतन वाले डीएनए का। बड़े दलित नेता व दलित पेंथर मूवमेंट के नेता दत्ताराव शिंदे यह सब देखकर ही भाजपा के कार्यकर्ता बने थे।

संविधान पर चर्चा में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में जो कहा उसके पहले 11 सेकंड के अंश को भ्रामक रूप से देशभर में फैलाया जा रहा है। इससे कांग्रेस, आंबेडकर जी को फैशन का विषय मानने के अपने चिर पुराने चरित्र को ही दोहरा रही है। गृहमंत्री के इस वक्तव्य को यदि पूरा सुनेंगे तो आंबेडकर जी के अपमान के सारे वहम दूर हो जाते हैं। अमित शाह ने कहा- हमे तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ-साथ आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये भी बताता हूं। आंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा।

आंबेडकर जी ने कई बार कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं। शाह ने आगे कहा, आंबेडकर जी को आश्वासन दिया गया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। आंबेडकर को आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

बार-बार संविधान और फैशन में डॉ. आंबेडकर का नाम रटने वाली कांग्रेस ने तो बाबा साहेब को संविधान सभा के 296 सदस्यों में डॉ. आंबेडकर को प्रवेश तक न मिलने देने के षड्यंत्र रचे थे। बाद में दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से वे येन-केन प्रकारेण संविधान सभा में प्रवेश कर पाये थे। डॉ. आंबेडकर बंगाल की जिस खुलना जैसोर सीट से संविधान सभा में पहुँचे थे, वह इकहत्तर प्रतिशत हिंदू बहुल थी। देश विभाजन में इक्यावन प्रतिशत हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में रहने देना तय हुआ था। केवल बाबासाहेब को संविधान सभा में घुसने से रोकने के लिए कांग्रेस ने बंगाल का यह इकहत्तर प्रतिशत वाला जिला पाकिस्तान को दे दिया ताकि डॉ. आंबेडकर की संविधान सभा की सदस्यता रद्द हो जाए।

आज आंबेडकर जी का नाम फैशन में लेने वाली कांग्रेस ने तो उनका चित्र तक लोकसभा में नहीं लगने दिया था। संसद में, गैरकांग्रेसी सरकार बनने पर ही उनका चित्र लग पाया था। भाजपा ने आंबेडकर जी से जुड़े पाँच स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबासाहेब लंदन में जिस घर में रहे, भाजपा सरकार ने उसका भी अधिग्रहण किया व उनके स्मारक के रूप में उसे लंदन तक में विकसित किया। भाजपा ने ही चैत्य भूमि को विकसित किया और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ स्वयं प्रार्थना के लिए गए। भाजपा ने दिल्ली के 26, अलीपुर रोड को भी विकसित किया, जहां बाबासाहेब ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। कांग्रेस के दुष्प्रचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी जी के इस ट्वीट (एक्स) का एक-एक शब्द एक-एक पुस्तक के बराबर है -

If the Congress and its rotten ecosystem think their malicious lies can hide their misdeeds of several years, especially their insult towards Dr. Ambedkar, they are gravely mistaken!

The people of India have seen time and again how one Party, led by one dynasty, has indulged in every possible dirty trick to obliterate the legacy of Dr. Ambedkar and humiliate the SC/ST communities.

देश विभाजन की जनक कांग्रेस के सामने बाबासाहेब प्रारंभ से ही अखंड भारत के पक्ष में थे। यह नेहरू जी को बहुत भयभीत करता था। नेहरू जी, आंबेडकर जी की प्रतिभा को जानते थे अत: वे उन्हें सत्ता की दहलीज़ तक भी नहीं आने देना चाहते थे। आंबेडकर जी मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किए जा रहे गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के प्रयासों के पुरजोर विरोधी थे।

आंबेडकर जी की पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में इसका पूरा विवरण है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के चलते कांग्रेस ने देश का विभाजन कर डाला। बाबासाहेब का यह स्पष्ट मानना था कि चूँकि धर्म आधारित विभाजन हुआ है अत: संपूर्णत: तुम उधर-हम इधर की नीति अपनाई जानी चाहिए। बाबासाहेब ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में भारत के धार्मिक आधार पर पूर्ण विभाजन के आशय से पृष्ठ 103 पर लिखा यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बनने से हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो जाएगा। आंबेडकर जी के इन्हीं मुस्लिम विरोधी विचारों के कारण से 'मुस्लिम तुष्टिकरण में लगे नेहरू जी व गांधी जी' आंबेडकर जी को आगे नहीं आने देना चाहते थे। इसी क्रम में मुंबई से दो बार आंबेडकर जी को चुनाव में षड्यंत्रपूर्वक हरवाया गया। इन दोनों बार के चुनावों में आंबेडकर जी की पराजय सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वयं मुंबई जाकर चुनाव प्रचार किया था व अपने विरोधी दलों से भी आंबेडकर जी को पराजित कराने हेतु मित्रतापूर्ण संबंध बनाए थे।

आज जो कांग्रेस और अन्य दल आंबेडकर जी का नाम फैशन या सत्ता मोह में ले रहे हैं, उन्हें इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि आंबेडकर जी केवल और केवल सम्मान का विषय हैं फैशन का नहीं!

ज्ञानेंद्र कुमार : कला की त्रिवेणी

राम प्रताप मिश्र साकेती

ज्ञानेंद्र कुमार के चित्रों और मूर्तियों का मुख्य विषय नारी संसार रहा है। उनके कई चित्रों को विशेष सम्मान मिला है,जिसमें उलझन नामक चित्र में नारी को पीले और कत्थई रंग से घूमती हुई तूलिका से उकेरा गया है जो अपने आप में विशेष है। इसी तरह अमूर्त चित्रण में प्रकाश की ओर कृति में चित्रकार ने प्रकाशीय रंगों का अद्भुत प्रयोग किया है। चित्र दुआ में चित्रकार ने समुद्री नीले रंगों का सार्थक उपयोग किया है। विश्वभारती शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त प्रख्यात चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार एवं साहित्यकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ज्ञानेंद्र कुमार अपनी कला के बल पर जिन विशिष्ट विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा, राजीव गांधी, उपराष्ट्रपति डॉ. बीडी जत्ती, डा.

मूर्त और अमूर्त चित्रण- दोनों विधाएं कला के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। परंपरागत से आधुनिक कला तक में पारंगत अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार ज्ञानेंद्र कुमार उत्तराखंड की पहचान हैं। वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) के मुख्य कलाधिकारी पद से सेवानिवृत्त ज्ञानेंद्र कुमार चित्रकला, मूर्तिकला और काव्य कला की त्रिवेणी के रूप में उत्तराखंड की कीर्ति विश्व भर में फैला रहे हैं।

ज्ञानेंद्र कुमार का जन्म 1 जून 1941 को हुआ था। ज्ञानेंद्र कुमार हिन्दी, अंग्रेजी और बांग्ला तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार हैं और तीनों भाषाओं में साहित्य रचना का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कला को व्यावसायिक रूप से जन सामान्य में प्रस्तुत करना उनकी विशिष्टता है। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आयी बाढ़ तथा इस विविषिका पर बनी उनकी लंबी कलाकृति वर्षों तक चर्चा का विषय रही है। ज्ञानेंद्र कुमार ने एमए दर्शनशास्त्र करने के बाद विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन से ललितकला का डिप्लोमा प्राप्त कर अपनी कला साधना प्रारंभ की। वन अनुसंधान संस्थान के मुख्य कलाधिकारी रहते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ललित कला ग्रीष्म अकादमी, आस्ट्रिया में अमूर्त चित्रकला संगोष्ठी में भाग लिया। मूर्तिकला एवं चित्रकला की नई संभावनाओं पर अध्ययन हाईवैकम कॉलेज आफ आर्ट टैक्नोलॉजी इंग्लैण्ड से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। विश्वविख्यात वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में मुख्य चित्रकला अधिकारी (वर्ष 1965 से 2001 तक) रहते हुए उन्होंने संस्थान को कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां देने का काम किया और वैज्ञानिक वानिकी में कला का योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेष कार्य किया। उनके इन्हीं महत्वपूर्ण कृत्यों के कारण उन्हें उत्तरांचल कला परिषद उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया जहां उनका लक्ष्य है कि वह उत्तराखण्ड में आधुनिक कला प्रवृत्तियों से कला प्रेमियों को परिचित कराने के साथ साथ प्रदर्शिनियां के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं।

ज्ञानेंद्र कुमार के चित्रों और मूर्तियों का मुख्य विषय नारी संसार रहा है। उनके कई चित्रों को विशेष सम्मान मिला है,जिसमें उलझन नामक चित्र में नारी को पीले और कत्थई रंग से घूमती हुई तूलिका से उकेरा गया है जो अपने आप में विशेष है। इसी तरह अमूर्त चित्रण में प्रकाश की ओर कृति में चित्रकार ने प्रकाशीय रंगों का अद्भुत प्रयोग किया है। चित्र दुआ में चित्रकार ने समुद्री नीले रंगों का सार्थक उपयोग किया है।

विश्वभारती शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त प्रख्यात चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार एवं साहित्यकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ज्ञानेंद्र कुमार अपनी कला के बल पर जिन विशिष्ट विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा, राजीव गांधी, उपराष्ट्रपति डॉ. बीडी जत्ती, डा. भगवत शरण उपाध्याय, डॉ. हरिवंशराय बच्चन, रानी एलिजाबेथ तथा जार्ज बुश शामिल हैं। देश-विदेश में अपनी कला प्रदर्शनियों तथा संगीत संध्या के माध्यम से ज्ञानेंद्र कुमार ने लोगों का दिल जीता है। जिन प्रमुख स्थलों पर ज्ञानेंद्र कुमार की कला प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं उनमें भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद नई दिल्ली का नाम प्रमुख है। यहां निर्भयाकांड के समय ज्ञानेंद्र कुमार की नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी का सम्मान हुआ। संचार माध्यमों में इसका विशेष प्रसारण हुआ। ज्ञानेंद्र कुमार के कला जीवन पर आधारित साक्षात्कार दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होते रहते हैं। उनके प्रभात गीत कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गाए जाते हैं।

ज्ञानेंद्र कुमार ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि वे चित्रकला, मूर्तिकला और काव्य कला के माध्यम से समाज को प्रेरित करते हैं। जो बात सीधे नहीं कही जा सकती वह चित्रों और कला के माध्यम से आसानी से व्यक्त की जा सकती है। ज्ञानेंद्र कुमार मानते हैं कि समाज में लगातार परिवर्तन हो रहा है। यह विकास और परिवर्तन कई मायनों में अनूठा है लेकिन यह भी सच है कि आज लोगों को कला, साहित्य और मूर्तिकला क्षेत्र के बारे में न तो जानकारी प्राप्त करने का समय है और न ही लोग इस क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं जबकि कला संसार ही जीवन का यथार्थ स्वरूप है। कला के बिना यह संसार आधूरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय कला में अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। भारतीय कलाकार वाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक भावों के अंकन में अपने मन को अधिक लगाते हैं। शांति निकेतन से निकले छात्र-छात्राओं ने कला के माध्यम से समाज को झंकृत करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि समकालीन भारतीय कला का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय और बहुत प्रयोगात्मक रहा है। इसमें अभी भी देश के लंबे और समृद्ध कलात्मक इतिहास के संदर्भ शामिल हैं।

आजकल

मोबाइल बन रहा जी का जंजाल

साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों के लिए जोखिम लगातार बढ़ रहा है। एक ओर लोगों के डेटा निरंतर चुराने की खबरें आती हैं, वहीं अब मोबाइल में बेतहाशा सेंधमारी होने लगी है। इसका अर्थ है कि लोगों की निजता खतरे में है। बैंकिंग लेन-देन से लेकर उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर है। मोबाइल उपयोगकर्ता की सभी जानकारियां पलक झपकते सेंधमारों तक पहुंच जाती है। इसके बाद क्या होता है, यह किसी से छिपा नहीं है।

फिलहाल तो इस खबर ने चिंता बढ़ा दी है कि हमारे यहां मोबाइल फोन में सर्वाधिक सेंधमारी हो रही है। 'जेडस्केलर थ्रेटलैब्ज 2024 मोबाइल, आइओटी एंड ओटी थ्रेट रपट' को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके मुताबिक, दुनिया भर में हुई सेंधमारी के क्रम में भारत में सबसे अधिक अट्ठाईस फीसद हमले हुए। मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए यह खतरे की घंटी है, तो दूरसंचार कंपनियों और मोबाइल निर्माताओं के लिए चेतावनी भी। उन्हें बढ़ते साइबर खतरों के बीच अब सुरक्षा उपाय के लिए नए कदम उठाने होंगे।

अंतरजाल की दुनिया में आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जरा-सी लापरवाही मुसीबत में डाल देती है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि आज के दौर में सभी गतिविधियां मोबाइल, लैपटाप अथवा कंप्यूटर में केंद्रित हो गई है। लोग अपने से संबंधित कई संवेदनशील जानकारियां मोबाइल में रखते हैं। एक रपट के अनुसार, वास्तविक बैंकिंग वेबसाइट की हूबहू नकल वाली वेबसाइट तैयार कर ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है। किसी अनजान लिंक पर पहुंचते ही साजिशों की घेराबंदी शुरू हो जाती है। मोबाइल 'स्पाइवेयर' से भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं की निजी जानकारियां गुप्त तरीके से चुरा लेता है। सबसे बड़ा खतरा वित्तीय धोखाधड़ी का है। आज जब पूरी बैंकिंग मोबाइल में सिमट गई है, तो ऐसे में यह सेंधमारी किसी को कभी भी संकट में डाल सकती है।

नदियों के मिलन से बहेगी विकास की धारा

प्रमोद भार्गव

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, कालीसिंध और चंबल का पानी एक बड़े जलस्रोत के रूप में बहता है। उपरोक्त नदियों को जोड़े जाने की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में रखी है। इसके प्रतीकस्वरूप तीनों नदियों के पानी को एक घड़े में भरा गया। इसके बाद भारत सरकार और राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना पर 72000 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी। इसमें मध्यप्रदेश के 13 जिलों के 3217 ग्रामों की सूरत बदल जाएगी। दोनों प्रदेशों में मिलाकर 27 नए बांध बनेंगे और 4 पुराने बांधों पर नहरों की जलग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ मौजूदा चंबल-नहर प्रणाली का उद्धार किया जाएगा। ये नदियां निर्धारित अवधि में जुड़ जाती हैं तो सिंचाई के लिए कृषि भूमि का रकबा बढ़ने के साथ अन्न की पैदावार बढ़ेगी।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान की जो परिकल्पना की थी, उसे नरेंद्र मोदी ने साकार करने की शुरुआत केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से कर दी थी। ये परियोजनाएं जल-शक्ति अभियान 'कैच द रन' के तहत अमल में लाई जा रही हैं। बाढ़ और सूखे से परेशान देश में इन नदी परियोजनाओं को जोड़ने का अभियान सफल होता है तो 57 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा।

दरअसल जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा-चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिये भेजा जाए। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है। हालांकि पर्यावरणविद् इन प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ने से इनकी अविरलता खत्म होगी व विलुप्त होने का संकट बढ़ जाएगा।

नर्मदा और क्षिप्रा नदियों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके थे। चूंकि ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में बहती थीं, इसलिए इन्हें जोड़ा जाना संभव हो गया था। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की तैयारी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बहुत पहले से जुटी थीं। इस परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ था। कालांतर राजनीतिक स्थितियां बदलीं तो परियोजनाओं पर सहमति बन गई। केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की ओर बहने के बाद बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। वहीं बेतवा नदी मध्य-प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना पर बांधों एवं नहरों का काम शुरू हो गया है।

दुनिया के महासागरों, हिमखंडों, नदियों और बड़े जलाशयों में अकूत जल भंडार हैं। लेकिन मानव के लिए उपयोगी जीवनदायी जल और बढ़ती आबादी के लिए जल की उपलब्धता का बिगड़ता अनुपात चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसे में भी बढ़ते तापमान के कारण हिमखंडों के पिघलने और वर्षा न होने के चलते जल स्रोतों के सूखने का सिलसिला जारी है।

वर्तमान में जल की खपत कृषि, उद्योग, विद्युत और पेयजल के रूप में सर्वाधिक हो रही है। हालांकि पेयजल की खपत मात्र आठ फीसदी है जिसका मुख्य स्रोत नदियां और भू-जल हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के दबाव के चलते एक ओर नदियां सिकुड़ रही हैं, वहीं औद्योगिक कचरा और गंदगी बहाना जारी रहने से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बेहद प्रदूषित हो गई हैं।

प्रस्तावित करीब 120 अरब डॉलर अनुमानित खर्च की नदी जोड़ो परियोजना को दो हिस्सों में बांटकर अमल में लाया जाएगा। एक प्रायद्वीप स्थित नदियों को जोड़ना और दूसरे हिमालय से निकली नदियों को जोड़ना। प्रायद्वीप भाग में 16 नदियां हैं, जिन्हें दक्षिण जल क्षेत्र बनाकर जोड़ा जाना है। इसमें महानदी, गोदावरी, पेन्नार, कृष्णा, तापी, नर्मदा, दमनगंगा, पिंजाल और कावेरी को जोड़ा जाएगा। पश्चिम के तटीय हिस्से में बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ा जाएगा। इस तट से जुड़ी तापी नदी के दक्षिण भाग को मुंबई के उत्तरी भाग की नदियों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की जलधारा पूर्व दिशा में मोड़ी जाएगी। यमुना और दक्षिण की सहायक नदियों को भी आपस में जोड़ा जाना इस परियोजना का हिस्सा है।

हिमालय क्षेत्र की नदियों के अतिरिक्त जल को संग्रह करने की दृष्टि से भारत और नेपाल में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों पर विशाल जलाशय बनाने के प्रावधान हैं। ताकि वर्षाजल इकट्ठा हो और उत्तर-प्रदेश, बिहार एवं असम को भयंकर बाढ़ से छुटकारा मिले।

इन जलाशयों से बिजली भी उत्पादित की जाएगी। इसी क्षेत्र में कोसी, घांघरा, मेच, गंडक, साबरमती, शारदा, फरक्का, सुन्दरवन, स्वर्णरेखा और दामोदर नदियों को गंगा, यमुना और महानदी से जोड़ा जाएगा। करीब 13,500 किमी लंबी ये नदियां भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं। वही 2528 लाख हेक्टेयर भूखंडों और वनप्रांतरों में प्रवाहित इन नदियों में प्रति व्यक्ति 690 घनमीटर जल है। कृषि योग्य 546 लाख हेक्टेयर भूमि इन्हीं नदियों की बदौलत सिंचित होती है।